श्री स्वराज कौशल (हरियाणा) : जरा यह बता दीजिए कि वे ए.आई.सी.सी. के मेंबर हैं या नहीं ...**(व्यवधान)** ...

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2002 AND THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2002 (Contd.)

श्री राजू परमार (गुजरात) : सभापति महोदय, डा. जटिया द्वारा यह जो संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। महोदय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो सरदार सरोवर परियोजना चल रही है, उसकी वजह से जो गांव डूबने जा रहे हैं, वहां के लोगों को गुजरात में बसाने के लिए और गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में उन्हें सम्मिलित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

सर, आप जानते हैं कि पहले भी कई नर्मदा डेम जैसे, सरदार सरोवर डेम जैसे कई डेम इंडिया में बने हैं। लेकिन जब ऐसे डेम बनते हैं तो उसकी वजह से लोगों पर इफेक्ट होता है। जो लोग आउस्टीज़ बनते हैं, उनको बसाने के लिए पहले इतना अच्छा प्रावधान कोई नहीं हुआ था। इस बार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव जो इस डेम के बनने से डूबने जा रहे हैं और वहां के लोगों को गुजरात में बसाया जाने वाला है, ऐसे लोगों को गुजरात की शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में इन्क्लूड करने के लिए माननीय मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एस.सी. और एस.टी. के लोग जब गुजरात की एस.सी., एस.टी. की सूची में इन्क्लूड होंगे तो नेचुरल है कि वहां की जो एस.सी., एस.टी. की सूची है, उसमें परसेंटेज भी बढ़ेगा। महोदय, इस बिल के द्वारा शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों का इन्क्लुजन गुजरात की एस.सी., एस.टी. की सूची में हो रहा है, उसके मुताबिक एस.सी. की जो फिगर्स बढ़ती है, जितनी पापुलेशन बढ़ती है, उतनी पापुलेशन का फिगर गुजरात की एस.सी. और एस.टी. की पापुलेशन में इन्क्लूड हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लेकर आएं और गुजरात में जो एस.सी. का सात परसेंट है, और एस.टी. का 14 परसेंट है, उसकी परसेंटेज को बढ़ाएं, तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा।

सर, आप जानते हैं कि अभी जो प्रावधान एस.सी./एस.टी. के परसेंटेज का है, वह 1971 के सेंसस के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन अभी जो 2001 का सेंसस हुआ है, उसमें एस.सी./एस.टी. की पापुलेशन काफी बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि जब 2001 का सेंसस हो चुका है और अभी 2002 चल रहा है तो जितना हो सके उतना सेंसस के मुताबिक एस.सी./एस.टी. की रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है, उसको बढ़ाया जाए। यह मैं आदरणीय मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के एक अहम इश्यु पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे गुजरात में 1976 में पार्लियामेंट के जरिए से एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें डांग डिस्ट्रिक्ट के जो मोची थे और उमरगांव तालुका के जो मोची थे, उनको गुजरात की एस.सी. की सूची में डाला गया था। आप जानते हैं कि पहले बोम्बे स्टेट था और जब बोम्बे स्टेट का विभाजन हुआ और उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट बने। बोम्बे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डांग के जो मोची थे और उमरगांव तालुका के जो मोची थे, वे वहां की एस.सी. की सूची में थे और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के मोची जब गुजरात में आ गये तो डांग के मोची और उमरगांव तालुका के मोची दोनों गुजरात की एस.सी. की सूची में डाले गये थे, लेकिन इससे पहले वहीं के लोग एस.सी. की सूची में थे। लेकिन पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट के जरिए पहले जो एरिया रेस्ट्रेक्शन था, वह एरिया रेस्ट्रेक्शन निकाल दिया गया और पूरे गुजरात के जो मोची थे, उनको एस.सी. का लाभ मिलने लगा। उसकी वजह से जो गुजरात के रियल एस.सी. हैं, उनके साथ काफी अन्याय हो रहा है। अभी जो मोची गुजरात के हैं, उनमें काफी वैल ऑफ लोग हैं, वे शैड्यूल्ड कास्ट के किसी फंक्शन में आते नहीं हैं, उनके साथ कभी कोई व्यवहार रखते नहीं हैं। तो जो वहां के रियल शैड्यूल्ड कास्ट हैं, वे मोची केवल डांग डिस्ट्रिक्ट और उमरगांव तालुका के ही लोग हैं और पूरे गुजरात के लोगों को इन्क्लुड करने की वजह से कई सालों से 1976 से लेकर आज तक 24 साल हो गये हैं, यह अन्याय रियल एस.सी. के लोगों के साथ हो रहा है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा, हमारी गुजरात की गवर्नमेंट ने भी जब से यह इश्यु खड़ा हुआ है 1976 से, तब से जो-जो सरकारें आई हैं, उन्होंने सेंटर के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को लिखा है कि एक अमेंडमेंट लाकर के पहले जो एरिया रेस्ट्रिक्शन था, उसको दुबारा से इम्पोज किया जाए। लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। माननीय जटिया जी के आने के बाद इस संबंध में बात आगे बढ़ी है और इसके लिए एक बिल भी वह लेकर आए हैं। यह बिल अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस और लेबर से वापिस मिनिस्टरी में आया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बिल के अमैंडमेंट को भी जल्दी से पार्लियामेंट में लाकर गुजरात के लाखों एस. सीज़ के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे दूर करें तो हमारे गुजरात के सभी शैडयूल्ड कास्ट उनके आभारी रहेंगे। दूसरा एक और अहम मसला मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शैडयूल्ड कास्ट शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ पार्लियामेंटरी कमेटी का सदस्य भी हूं। इस पार्लियामेंटरी कमेटी के तहत भारत के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एल.आई.सी., पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हम लोग विज़िट करते हैं और जब हमारी विज़िट होती है तो हम एस.सी. एस.टीज़ के मामलों को ऐक्ज़ामीन भी करते हैं। उसमें हमें एक चीज़ जो खास देखने को मिलती है, वह यह है कि कई लोग जो शैडयूल्ड कास्ट्स के नहीं हैं, वे भी फेक सर्टिफिकेट बनवाकर शैडयूल्ड कास्ट के बैनीफिट्स लेने की कोशिश करते हैं और गलत सर्टीफिकेट देकर वे लोग नौकरियों तक में आ जाते हैं। हमने ऐसे कई केसिज़ देखे हैं कि सालों तक उनके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होती है, उनको डिसपोज़ ऑफ नहीं किया जाता है। एक जगह हमने जांच की और पाया कि तमिलनाडु में ऐसे तीन हजार से भी ज्यादा फॉल्स कास्ट सर्टीफिकेट्स के केसिज़ हमारे ध्यान में आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे फाल्स सर्टीफिकेट के जितने भी एस.सी., एस.टीज़. के केसिज़ हैं, उनकी आपके मंत्रालय के थ्रू जांच की जाए, जांच के बाद इतना लम्बा पीरियड न रखें और तुरन्त उस संबंध में टाइम बाउंड प्रोग्राम करके, उनके संबंध में जांच करके फेक सर्टीफिकेट्स के जरिए जो लोग सर्विस में आ गये हैं, उनके संबंध में ऐक्शन लिया जाए। ऐसी मैं

आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। एक और बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि आपको मालूम है कि अभी कई पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ का डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है। अभी हमारी पैट्रोलियम कमेटी में भी उन्होंने बताया कि वे लोग प्राइवेट कम्पनीज़ को रिटेल आउटलैट गैस एजेंसी खोलने के लिए उनको लाइसेंस देने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब डिसइनवैस्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ का हो रहा है और हो गया है, उसमें शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ के रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, उसका प्रोटैक्शन अभी नहीं हुआ है। जब डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है तो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ को संविधान के द्वारा जो प्रावधान हुआ है, उसका बैनीफिट उनको डिसइनवैस्टमेंट करने के बाद, प्राइवेट कम्पनीज़ को देने के बाद भी वह रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूं। इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम मिनिस्टरी प्राइवेट कम्पनीज़ को रिटेल आउटलैट खोलने के लिए जो थोड़े ही समय में लाइसेंस देने जा रहे हैं उसमें जो 25 प्रतिशत रिटेल आउट में पैट्रोलियम मिनिस्टरी के जरिए प्रावधान है, शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज़ का है, हैंडीकैप्ड का है, विडोज़ का है, ऐक्स सर्विसमैन का है, ओ.बी.सी. का है। जब भी आप रिटेल आउटलैट खोलने के लिए प्राइवेट कम्पनीज़ को लाइसेंस दें तो इस प्रावधान को बरकरार रखना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा। आप यह जो बिल एस.सी. की सूची में डालने के लिए लाए हैं, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय सदस्यगण, जैसा कि सभापति महोदय के कक्ष में सुबह यह बात हुई थी कि चूंकि ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बिल हैं इसलिए इनको पास कर दिया जाए और ज्यादा बहस न की जाए लेकिन मेरे पास 14 माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके आप ही सहयोग करें और थोड़े -थोड़े में अपनी बात रख दें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is not a controversial Bill. Everybody wants that new castes or new sub-castes should be added. That is why a large number of inclusions have taken place. Besides, we are having a heavy business today. We have to discuss the working of the Ministry of Agriculture, the Multi-State Cooperative Societies Bill, 2000. Moreover, the House has to be adjourned at 6.00 p.m. Therefore, keeping all these things in view, if the hon. Members agree to approve this Bill without much discussion, it will be appreciated.

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, एक बात मुझे कहनी है कि जितने कम समय में बात रखी जाए, वह ठीक है लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ जैसा बिल हमेशा इस हाऊस में नहीं आता है और अगर हम टाइम के चक्कर में इसी के ऊपर हमला करते हैं तो बाहर इससे हाऊस का संकेत ठीक नहीं जाएगा। इसलिए आपने जैसा कहा है कि थोड़े कम समय में सदस्य बोलने की कोशिश करें, वह ठीक है। लेकिन इस पर डिसकशन तो होना ही चाहिए, बिना डिसकशन के यह बिल पास नहीं होना चाहिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): जहां डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो, वहां तो डिसकशन होना चाहिए, जहां डिफरेंस ऑफ ओपीनियन नहीं है वहां डिसकशन की ज़रूरत नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ठीक है, थोड़े-थोड़े समय में सब अपनी बात को रखें।

SHRI SUDARSHAN AKARAPU (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the two Bills which have been introduced by the hon. Minister, wherein, around 37 castes, *i.e.*, 18 Scheduled Castes and 19 Scheduled Tribes are being included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is good that the people who were neglected socially, economically and politically, for a long period, without any basic amenities, have been identified and included in the list so that they can prosper and develop on par with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and enter the mainstream of the society.

According to the latest Census report, the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is at present 24.75 per cent of the total population of the country. But the percentage of reservation is 22.5 per cent. As the percentage of reservation is not on par with the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the people belonging to the reserved category are not getting adequate opportunities in the educational institutions and in the employment sector, where the thrust is more towards privatisation. This is against the spirit of our Constitution. By adding more number of castes to the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the situation worsens, causing unemployment and non-availability of educational opportunities to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My request is to increase the percentage of reservation bring it on par with the SC/ST population, *i.e.*, 25 per cent, at present.

Merely adding castes to the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not going to help the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The programmes envisaged for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are to be implemented in their true spirit, in order to bring them above the poverty line. Here, I would like to mention with pride that our Government under the leadership of hon'ble Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, has increased the budgetary allocation by 15 to 20 per cent every year for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The residential schools which have been

started, with all facilities, for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are giving good results.

Our Chief Minister envisaged a new programme called "MUNDADUGU", meaning taking a step forward, by providing a budgetary allocation of Rs.100 crores, over and above the normal budgetary allocation, for the development of Scheduled Castes; and another programme called "CHAITANYAM" for the development of Scheduled Tribes.

In respect of the Special Component Plan (SCP) and the Tribal Sub Plan (TSP), though the overall achievement is 4 per cent, in the country, in the State of Andhra Pradesh, it is 10.6 per cent, as per the latest figures given by the National Institute of Rural Development, Hyderabad. This shows the good performance by the Andhra Pradesh Government in the matter of development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Central Government should take necessary steps to persuade all other State Governments to implement the Special Component Plan and the Tribal Sub Plan in letter and spirit.

Finally, I request the Government of India to implement sincerely all the programmes envisaged for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I, on behalf of my Party, support these two Bills, and look forward for another Bill to increase the percentage of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on par with the population percentage. Thank you, Sir,

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, identifying any particular community and including it in the Constitutional Order will be meaningful only if the benefit reaches the concerned persons. Otherwise, it will only remain in paper. I am happy that the Law Minister is present in the House. He has to do something in the matter. After so many decades after Independence, the real benefit has not reached the concerned people. I can cite a number of examples to prove that.

Sir, Tamil Nadu is a pioneer in the matter of giving reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We are giving 69 per cent of reservation for a long time. This is not a new policy for us. So many communites in Tamil Nadu have benefited as a result of this. But, unfortunately, while we passed a welfare legislation as long ago as 1994 in giving 69 per cent reservation, which includes the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it was stayed by the Supreme Court. As a result, reservation up to the level of 50 per cent alone is being maintained. There

are so many legislations pending in the Supreme Court. The Union of India can easily plead with the Supreme Court to see that they are listed early for a decision so that the real benefit reaches the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes. But no effort seems to have been made by the Union of India to see that those orders are vacated. This is a matter, where I feel, the Union of India has to take some steps.

In addition to that, when the AIADMK was a member of the BJP-led Government at the Centre, there was an undertaking given in the National Agenda itself that whichever States are implementing above 50 per cent reservation, there would be a legislation by the Central Government itself to protect the reservation over and above 50 per cent already implemented by the respective States. Such a legislation has not till now been brought forward. I do not know the reason for that. Therefore, my request, through this House, to the Government is that there is no point in merely including names in the Scheduled Castes Order or in the Scheduled Tribes Order. The best way is to see that the real benefit reaches them. Wherever court cases are pending, they should be got vacated and the benefit given to the public. Earlier, Dr. Jayalalithaji had enacted a welfare measure, but it has now been stalled. Therefore, the Union of India should take effective steps to see that the stay is vacated and the benefit reaches the public, not only in the matter of employment and education, but also in other social spheres.

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जटिया साहब ने अनुसूचित जाति-जनजाति का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं तथा साथ ही यह मांग भी करती हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को आज तक जो आरक्षण दिया गया है, उसका लाभ अनुसूचित जाति में आने वाले, उसका लाभ लेने वाले जो वास्तविक लोग हैं, उन्हें इसका लाभ बहुत कम मिला है। अभी एक एम.पी. साहब ने, गुजरात वालों ने बताया कि दूसरे लोग डबल-डबल जातियों में जुड़ जाते हैं। उदाहरणतया एक तरफ तो भील जाति अनुसूचित जाति में जुड़ गई है और दूसरी तरफ आदिवासी जनजाति में भी जुड़ गई है। इस प्रकार से दोहरा लाभ लेने से अनुसूचित जाति के जो सही लोग होते हैं वे उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि एक तो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण कोटा है उसे बढ़ा दिया जाए, हालांकि जो दिया गया है यदि उसे भी सही ढंग से लागू किया जाए तो उन्हें अपने आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

दूसरी बात यह है कि कागजों पर जो रिजर्वेशन होता है वह मन को दुख देने जैसी बात होती है। क्योंकि जब तक अनुसूचित जाति के शिक्षित लोगों को सरकार नौकरियां नहीं देगी, बैकलाग पूरा भरा नहीं जाएगा तब तक इस आरक्षण का फायदा नहीं है। इसलिए मैं जटिया के इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूं और वहीं तहेदिल से मांग करती हूं कि अगर आपको आरक्षण में ये सब चीजें लागू करनी हैं तो इनको सख्ती से लागू करें। दूसरी बात जो अभी निम्नलिखित

प्रदेशों में आपने जातियां अंकित की हैं उनमें मुझे अनुसूचित जाति की दो जातियां देखने को नहीं मिलीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेघवाल और मेघवंशी जो सही में अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको भी इस लिस्ट में जोड़ा जाए ताकि इन प्रदेशों में इन अनुसूचित जाति के लोगों को भी पूरा लाभ मिले। मैं इसी आग्रह के साथ आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने थोड़ा मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): I thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity. I will be very brief.

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2002 is to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002 is to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to provide for inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra who have been displaced due to the Sardar Sarovar Project on the Narmada River and are settled or may be settled in the State of Gujarat, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to the State of Gujarat.

I welcome both the Bills. I would like to make only one submission. As per the provisions in the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002, if persons from Madhya Pradesh and Maharashtra are settled in Gujarat, they are deemed to be belonging to the Scheduled Castes. On the other hand, if they are settled in some States other than Gujarat, they are not deemed to be so. This is a great difficulty which I am able to feel in this Bill. If the persons displaced settle in Gujarat, they will be deemed to belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; but if they settle in some other States, they will not be deemed to belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes! The displaced persons are in utter poverty having no means of livelihood. They belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, my plea is that wherever they may settle, they should be deemed to belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their place of settlement should not be limited to Gujarat.

Sir, I have another point. That relates to origin and migration. This is one of the important questions discussed for a long time in India. Suppose a person belongs to a Scheduled Caste in Tamil Nadu. If he migrates and settles in Pondicherry, he is not a Scheduled Caste man! Also, if a person belonging to a Scheduled Caste from Pondicherry settles

in Tamil Nadu, he will not be deemed to belong to a Scheduled Caste. It is said that always the place of origin, and not the place of migration, should be taken into consideration for demarcation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This anomaly is pending a final decision before the Supreme Court. I request the hon. Minister to take a positive decision on this aspect. A lot of people are suffering because of the existing provisions.

Finally, I would like to say this. We are including a lot of people in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The percentage is now fixed at 15 for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If we go on increasing the number of such Castes and Tribes in the list, we have also to increase the percentage. This point may also be considered by the hon. Minister. Thank you.

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित दो बिल सदन में लाए गए हैं। एक बिल का संबंध सरदार सरोवर परियोजना से है जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो विस्थापित हुए हैं और गुजरात में बसे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए है और दूसरा कुछ समुदायों - जो आठ समुदाय उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि से हैं उनको अनुसूचित जातियों में शामिल करने के प्रस्ताव के बारे में है। मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

महोदय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की श्रेणियों में रखा गया है। 1950 में पहली बार यह सूची अधिसूचित की गई और उसके बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के समुदायों को रिज़र्वेशन का लाभ मिल रहा है। मगर मैं महसूस करता हूं कि उस कानून से जितना लाभ उनको मिलना चाहिए था, जितनी हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए थी, उतनी उनको नहीं मिली है। महोदय, मैं दो वर्षों तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लियामेंटरी कमेटी का सदस्य था। उसके निरीक्षण दौरे में जहां भी मैं जाता था तो बैकलॉग के बारे में जब चर्चा करता था तो यही कहा जाता था कि फिट कैंडीडेट्स नहीं मिल रहे हैं जबकि इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आज ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें पढ़े-लिखे लोग नहीं हों। आज जागरूकता आई है और अच्छी संख्या में लोग पढ़ते हैं, मगर अभी भी कोई न कोई तिकड़म करके उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके जो अधिकार हैं वे सुरक्षित और संरक्षित रहें, यह सरकार को देखना चाहिए। अभी भी जुडीशियरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो ऊंचे-ऊंचे पद हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत कम है। महोदय, मेरे सामने 13वीं लोक सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का दूसरा प्रतिवेदन है। मैं उसमें से 3-4 पंक्तियां पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। "देश में सभी स्तरों पर विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और समूहों से आए न्यायाधीशों की आवश्यकता है। न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में संविधान की मूल भावना का पालन किया जाना चाहिए। "उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 5 पर लिखा है कि "सरकार ने व्यवहारिक रूप से आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के प्रश्न के संबंध में कथनी कुछ और तथा करनी कुछ और की

नीति अपनायी है। सरकार को इस रूप में बदलाव लाना ही होगा। न्यायिक सेवाओं को विशेष रूप से राज्य की न्यायिक स्कंध को आरक्षण की परिधि में लाने के लिए संविधान के संबंधित अनुच्छेद अर्थात् 124 और 127 में उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्चतर न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उचित कार्यकरण के साथ ही सिद्धांतों की व्याख्या करने हेतु एक न्यायिक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए। "महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी जो ऊचें पद हैं, यूनिवर्सिटी हो या सेना के पद हों या न्यायालय के पद हों, उन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि ऊंची जातियों के लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र ले कर एस.सी. एस.टी. के नाम पर नियुक्तियां कराई हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, आप देखेंगे कि नाम किसी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब का है और वह किसी बड़े आदमी के कब्जे में होते हैं। तो आरक्षण की सुविधा के बावजूद भी इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। महोदय, मैं मंत्री जी का एक विशेष बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो एक राज्य में तो पिछड़े वर्ग में है और दूसरे राज्य में वे शैड्यूल्ड कास्ट में हैं। मैं आपको एक जाति के बारे में बताना चाहता हूं। एक निषाद, मल्लाह, केवट जाति होती है, मुख्य रूप से इनका पेशा मछली मारना, नाव खेना है और उसी का एक समुदाय एग्रीकल्चर अर्थात् खेती का भी काम करता है। महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में निषाद, मल्लाह, केवट पिछड़े वर्ग में है और दिल्ली व पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में है। यह जो विसंगति है कि एक राज्य में एक समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति में और दूसरे राज्य में दूसरे वर्ग में रखा जाता है, इसे सरकार को देखना चाहिए। इन समुदायों के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी है, रहन-सहन व व्यवहार भी एक जैसा है तो सभी राज्यों में इन्हें यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए। अगर शेड्यूल्ड कास्ट के हैं तो सभी राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी भी कई राज्यों से कुछ जातियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास रिकमंडेशंस आ रही है तो उन रिकमंडेशंस पर विचार कर उन जातियों और समुदायों को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अभी एक माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे थे कि जैसे-जैसे इन समुदायों के लोगों की संख्या बढ़ती है, उनका आरक्षण का कोटा भी बढ़ना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA (Assam): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002. I rise here to make my maiden speech on this Bill. I support the Bill because it grants the status of Scheduled Tribe and Schedule Caste to some people who want to settle in Gujarat, who were displaced from the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, recently, due to the Government's decision to construct the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada. The decision of the Government to grant them the SC/ST status was long over due. It is their legitimate right. It may be bitter for the Government to swallow it; but the

reality is that, after the Independence of the country, the Scheduled Tribe and the Scheduled Caste people have been the victims of such kind of construction of dams and coal mining. Several such instances are found in the present Jharkhand area and in the North-Eastern Region. The right to land and property is frequently seized from the tribal people. The loss of right to land means, the loss of existence, culture, identity and everything for the tribals.

In our Constitution, there are several words defining some laws for the protection and preservation of tribal rights, culture, language, identity and everything. But, time and again, these laws are violated or ignored by the Government themselves. The evacuation of lakhs of people from the embankments of Narmada river recently is a good example of it. Very regretfully, the Government had declared the construction of a dam over Pagladia river in Assam, particularly in the district of Nalbari, whereby more than one lakh indigenous Bodo tribals and others are going to be displaced for the benefit of a very few people. Why have the tribals become a permanent target of such kind of dam and coal mining projects? Is it not a policy of negation of human rights to the indigenous tribal people?

The very essence of the concept of a welfare country has already been diluted and the tribal people are denied their rights in every sphere of their life. In our country, as per the 1991 Census, the tribal population was 8.08% of the total population. But the real percentage of the tribal population may be higher than that, because lakhs of tribal population remain uncounted for many reasons. The reservation for the tribal people is only 7.5 per cent and there is no reservation policy in the private sector for the tribals. Whenever the tribal people struggle for their political, Constitutional and human rights, they are brutally suppressed and they are denied their rights. For example, more than three-decade old demand of the indigenous Bodo people of Assam for a Bodoland has been denied totally, whereas the same Government has conceded the demand for creating new States of Jharkhand, Uttaranchal and Chattisgarh. Till today, the Government has failed to resolve the Bodo problem in Assam, as a result, development and peace have been affected in the region and the regional imbalance has increased.

If the country has to be developed fully, people belonging to the weaker sections have to be developed equally, on a par with the other advanced people. Illiteracy, unemployment among the educated tribal youths and discrimination in every sphere of their life have brought great

disillusionment to the tribal people. The essence of modern education, economic liberalisation and globalisation are still a distant dream only for them. They are yet to receive even primary education fully. These are the reasons for the present tribal unrest in the country.

Sir, the timely move of the Government to grant Scheduled Caste and Scheduled Tribe status to the displaced people in the State of Gujarat is a welcome step. But I am equally concerned with the future implication of the Bill which was moved. If the same is going to have an equal effect in other parts of our country, in future, then, it may create a serious crisis, with political ramifications in some States. In the case of Assam, a large number of people are migrating to Assam from the neighbouring States and the neighbouring countries. They are migrating to Assam, not because of their displacement due to construction of a dam or any other reason, but they are migrating to Assam in search of land and work. There is a large-scale migration. If the tribal people, who have migrated to Assam--they are very large in number--are given the same tribal status, the original tribal groups' interests may be affected. While considering the question of application of this Bill to the other States, the Government will have to be very cautious.

Lastly, while supporting this Bill, I, once again, request the Government not to continue with this kind of policy of uprooting the tribal people from their own land, since it will go against articles 14 and 15 of the Constitution. Frequent displacement of tribals have already hampered their economic development, stability and growth. Thank you.

*SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Honourable Chairman Sir, I rise to support the bills regarding Scheduled Caste and Scheduled Tribes. I also thank the Honourable Minister for bringing these two bills. A sizeable portion of socially and economically backward people will get recognition as Scheduled Caste and Scheduled Tribe with the help of these bills.

Chairman Sir, it is most lamentable that even after 55 years of our independence, socially backward people could not be elevated to the desired level of economic and social goals. Some of them have been recognized as SC and STs and hence given some facilities. Since the development is not yet complete, some facilities have to be provided for them.

---

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

Under the present economic structure of our country, most of the people are facing difficulties. If we do not go for a change in economic structure, their condition cannot be changed. People belonging to other sections of the society often vent their displeasure at the special facilities being provided to SCs and STs. This is not desirable. Such types of facilities should continue in a country to elevate downtrodden people to a socially and economically desired level.

People belonging to the Chain community who live in Malda, Murshidabad, Nadia, North and South Dinajpur in West Bengal had long been fighting for getting recognition as Scheduled Caste. I am happy that they have now been given this recognition. Three years ago, a unanimous resolution was passed in West Bengal Assembly to provide them this recognition. The Registrar General of India endorsed it.

Besides these, the Layek community and some other backward communities of West Bengal have been fighting with a demand to be recognized as Scheduled Caste and Scheduled Tribe. The West Bengal Government has provided many facilities to the Deshwali Majhi communities, who have been deprived in many spheres of life, through the Adibasi Welfare Organization. The West Bengal Government has tried its best to give humanly status to the people belonging to SCs and STs. It was unthinkable before 1977. These people were not given the due social status at that time.

The Rajbanshi community of North Bengal and also the people belonging to SC and ST were long deprived of economical and social status. But after 1977 they had a taste of humanly status and also got land through the land reforms movement. Yet it cannot be claimed that all the problems being faced by them have been solved. It can rather be said that the people of this area, who have long been discriminated on the developmental front, still live with displeasure. Despite the honest will of the State Government, they feel angry over the lack of communications system that comes under the purview of the Central Government.

People belonging to SC and ST living in North Bengal are therefore actively participating with other communities in demanding overall development including demands regarding railways and communication facilities. They are staging movements for successful completion of Teesta project to provide irrigation for agriculture. Incidentally, the Teesta project is

a project of the Central Government. Moreover, people with vested interests are trying deliberately to create rifts among them.

Honourable Chairman Sir, I would have been happier if a comprehensive bill covering the whole country were introduced here. At present, different States follow different laws in this regard. For example, Rajbanshi community in West Bengal belongs to Scheduled Caste. But in Meghalaya, they are recognized as Scheduled Tribe. At the same time, in Assam they were previously recognized as general and now as OBCs. A Commission was constituted in 1996 under the Chairmanship of the Honourable Member of Parliament in Lok Sabha, Shri Amar Roy Pradhan. Despite the recommendation made by this Commission and despite the prevailing social and economic backwardness of the community, Rajbanshis have not been given the status of Scheduled Tribe. In Bihar and Orissa, they are still being identified as general only. Many people were displaced from Madhya Pradesh and Maharashtra to Gujarat owing to the Sardar Sarovar Project. The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Order (Amendment) Bill 2002 has provisions to maintain the same recognition to those displaced persons belonging to SC and ST in Gujarat also. I support this provision and would also like to say that a comprehensive bill should be introduced to provide for similar facilities in every case. For example, the Namasudra, Kaibarta and other communities in West Bengal have been included as Scheduled Caste. Of those communities who were displaced to Dandakaranya, the Andamans, Bethiyar and other places on government initiative, but they have not been given the SC status. People belonging to SC and ST in Madhya Pradesh who were long ago employed in the tea gardens of Assam, were also not recognized as SC or ST. The system of treating a case so differently in the same country should be changed forthwith.

Sir, before I conclude I would like to say that the socially backward people should be recognized as Scheduled Caste and Scheduled Tribe and be given special facilities and opportunities. But this cannot be enough. A long period of 55 years has passed after getting independence. The government of the land should really have to take initiatives to elevate them socially and economically. A comprehensive plan package should be introduced in this direction.

I would also like to point it out to the Honourable Minister that the rate of employment in the country has almost touched the zero level. The dependence on import has increased. What is the relevance of reservation

1.00 P.M.

in employment under this circumstance? If we deal with a zero, the result will also get down to zero whatever the rate of reservation is. Hence the need of the hour can only be systematic measures for their development. Otherwise everything will just remain paperwork.

I once again thank you and conclude my speech.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय सदस्यगण, माननीय सभापति जी के कक्ष में यह निश्चय हुआ था कि आज भोजनावकाश न हो क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी है। एक तो कोऑपरेटिव वाला बिल है, दूसरा कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर भी चर्चा होनी है। इसलिए अगर माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो आज भोजनावकाश नहीं होगा। प्रो. रामगोपाल यादव जी, आप बोलिए।

प्रो. रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशनल ऑर्डर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, वैसे तो इतनी बड़ी सूची में कुछ नाम और जुड़ जाएं, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं का कौन सा उद्देश्य था कि उन्होंने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा?

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि सदियों से हमारे देश में समाज का एक वर्ग ऐसा रहा है जो न केवल उपेक्षित रहा है, बल्कि लगातार उसका शोषण और उत्पीड़न हुआ है। इसीलिए जब अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, इसे मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया गया था तो कुछ लोगों ने यह कहा था कि इसका क्या औचित्य है, इससे कौन सा अधिकार मिलता है? उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे कई प्रमुख संविधान निर्माताओं ने इस बात का उल्लेख किया था और यह कहा था कि यह देश ऐसा है जिस पर प्रजातंत्र का महल खड़ा हुआ है लेकिन बेसिकली उसकी नींव अलोकतांत्रिक है। इसलिए अगर संविधान में सेफगार्ड्ज़ नहीं होंगे, अगर संविधान में प्रोविजंस नहीं होंगे, तो चाहे हम कुछ भी कहते रहें, जो सदियों से शोषित और पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल सकता, उनको संरक्षण नहीं मिल सकता, उनको उनका हक नहीं मिल सकता। प्रश्न यह है कि जो परिस्थितियां हैं और जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए, जिस उद्देश्य के लिए यह सूची है जिसमें अनुसूचित जाति की तमाम जातियां रखी गई हैं, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है? मुझे याद है जब इस विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ हुई थी, तब संघ प्रिय गौतम जी ने इस तरफ इशारा किया था, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इस सूची में जो जातियां इन्क्लूडिड हैं, वे इसलिए इन्क्लूड की गईं थीं, ताकि नौकरियों में उनको आरक्षण मिले, स्पष्ट प्रावीजन्स हैं। लेकिन जब नौकरियां ही कम होती जा रही हैं, लिबरलाइजेशन के चलते जिस तरह से गवर्नमेंट में सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है, आप और हम अखबारों में लगातार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हर राज्य नौकरियों में कटौती कर रहा है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, संविधान के ज़रिये से जो सेफगार्ड प्राप्त हैं नौकरियां प्राप्त करने के लिए, दलित और शोषित, पीड़ित लोगों को, वह सब स्कोप खत्म होता जा रहा है। प्राईवेट संस्थाएं, प्राईवेट कम्पनियां आरक्षण की सुविधाएं नहीं दे रही हैं। जब तक गवर्नमेंट प्राईवेट कम्पनियों में नौकरी के लिए आरक्षण की

व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक कुछ और जातियों को, जो उपेक्षित जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति की सूची में रखने मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी सरकारी नौकरियां तो कम हो रही हैं। केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा था, वह भी खत्म हो रही हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नई पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही हैं। कम्प्युटराइजेशन की नीयत ही अनइम्पलायमेंट पैदा करना है, इसके ज़रिए से तो अनइम्पलायमेंट पैदा हो ही रहा है। लेकिन जो भी नौकरियां हैं, उनमें व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है और इस पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करें। जो प्राईवेट कम्पनियां हैं, जो निजी कम्पनियां हैं, उनमें आप आरक्षण की व्यवस्था करें तभी इन जातियों को कुछ लाभ मिल सकता है।

हर बार सेंसस होता है, जनगणना होती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की तादाद का पहले जो परसेंटेज था, उसकी कुल जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज में वृद्धि हुई है। उपसभाध्यक्ष जी, आप जब स्वयं उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के मंत्रिमंडल में थे, तो जनसंख्या जिस तादाद में अनुसूचित जाति और जनजाति की बढ़ी है, तुलनात्मक दृष्टि से, उस बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर उसी परसेंटेज में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था आपने बढ़ाई थी। मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह जो संख्या बढ़ गई है, उस पर आप जनगणना के आधार पर विचार करें क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था है इसलिए जो एक्चुवल जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति की है, उसके आधार पर आप उनको आरक्षण दें, उनकी संख्या पहले से ज्यादा है आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे दो प्रमुख सुझाव हैं। प्राईवेट कम्पनियों, निजी कम्पनियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म होता चला जा रहा है। जब नौकरियां ही कम होती चली जा रही हैं तो आरक्षण मिलने का सवाल ही नहीं है। जो जनसंख्या अनुसूचित जातियों की बढ़ी है, उसके आधार उनके आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ और उपेक्षित जातियों को संविधान की अनुसूचित जाति/जन जाति की सूची में रखा है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय श्री गांधी आज़ाद - अनुपस्थित। माननीय मिर्जा अब्दुल रशीद - अनुपस्थित। माननीय वीरभद्र सिंह।

SHRI BIRABHADRA SINGH (Orissa): Mr. Vice Chairman Sir, I rise to support. The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002. I would like to speak in Oriya while participating in the debate on this bill. This is a long over-due amendment bill. There is an urgent need to uplift certain sections of people belonging to SC/ST communities, who have been deprived of the benefit of reservation facilities after the country became independent. They are still lagging behind in social, educational and economic sphere. It is also true that many people belonging to SC/ST communities have reaped the benefit

* English translation of the original speech delivered in Oriya.

of reservation facility provided by our constitution. But unfortunately, there are certain people belonging to SC/ST communities who have not got the benefit of such reservation facilities. They are living in a very miserable condition in the society.

Mr. Vice-Chairman Sir, I shall not take much time of the house. I am really grateful to the honourable Minister for bringing such an important bill to the House. I urge upon the Hon'ble Minister to make a detailed study and survey of the recommendations of various State Governments with regard to the inclusion of various SC and ST communities in the ST/SC list. In this connection I would like to give two to three suggestions for the consideration of the Hon'ble Minister, Firstly, for example,there is a tribe called 'Bhumija' in Orissa to which I myself belong. This tribe also exists as a ST in Bihar and Madhya Pradesh. But unfortunately poor people of this tribe who migrated to Assam in the past as tea-garden labourers and as labourers to Andaman for livelihood are not recognized as ST in those states. They are the citizens of free India. It is a matter of regret that they are not listed as ST. It is necessary to enlist them as ST.

My second suggestion is with regard to third generation SC/ST children who have got the benefits of reservation by becoming well placed Class I and Class II officers as well as Members of Parliament and State legislature should be excluded from getting the reservation facilities in future. They should not be given the benefits of reservation because such reservation facilities are meant for the poor and deprived. Within our limited resources only those SC and ST people who are really deprived and downtrodden should be provided with such a facility. Therefore the 'Creamy layer' among the SC/ST should be excluded from getting this benefit. The Government is duty-bound to uplift the poorest of the poor. There is an urgent need to investigate the recommendations sent by various state governments in this regard and enlist such poor castes in the SC/ST list. They have to be brought at par with members of other castes who have advanced socially, Educationally and economically. These third-generation SC/ST people who are now socially and economically well of should be excluded from SC/ST list. There is a need to formulate norms for 'defining Creamy layer' among SC/ST people.

Thirdly, I support the views of my previous speaker Shri Ram Gopal Yadav to go in for a census of ST and SC people in the country. There is a need to provide reservation in jobs for SC and ST people not only in government sector but also in private sector.

While concluding I support the bill once again and express my gratitude to the Honourable Minister for bringing this bill.

Mr. Vice Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in this debate.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. While complimenting the hon. Minister, Dr. Satya Narayan Jatiya, for bringing such Bills, I will say that it is somewhat a consolation in a situation of vast deprivation of the people of this country. I remember Shakespeare, who says, 'there is much ado over nothing.' In fact, this is a social problem. This problem of discrimination, by way of caste, by way of religion and by way of other things, is a social problem. Unless we can effect some positive progressive social changes, we cannot really take care of these problems. These are only some cosmetic changes that we are trying to make, keeping the entire fabric of the society intact. In fact, what is against these poor people? I do not have the time to dwell upon all these matters, because these Bills are very small ones. I also should not take much time of the House, even though I am in a position to speak on this subject, for hours together. I will just try to point out some important points on the Bills which are apprehending me.

My other colleagues have pointed out that jobs are not being generated at all. So, what are you doing for these SC/STs? Some new number of people are being branded or stamped as SC or ST to allow them to take the privilege with some scope of job. But, there is no scope of job. The hon. Prime Minister has announced that there will be a reduction of 2 per cent in the Government employment every year and we presume, or, it is assumed that three per cent of the people in the Government retire every year. So, there is five per cent reduction in the net employment. But the job generation is less than zero. Even if we reserve 100 per cent jobs for the SC/STs, some new names have been included in the Bills, but the jobs obtained will be less than zero. So, the situation is terrible. I am convinced that majority of these SC/STs or the Backward Class are poor. A majority of them are poor. And the poor people are languishing. In this set up, the poor are languishing. And the policies of the Government of India are facilitating a situation where the poor have to languish more. I will, certainly, say that instead of this sort of palliative measures, instead of this sort of cosmetic measures, a comprehensive Bill must be brought forth, in which these social problems can be taken care of by the hon. Minister. I do not have any confidence in the NDA

Government. But I have a little confidence in Dr. Satya Narayan Jatiya, he is a person who has got the ability to bring forth a more comprehensive Bill by which this situation can really be taken care of. I request him to do so. And, through his Ministry, a social movement can be initiated. Some programmes can be initiated.

Some questions were raised in Parliament with regard to Government jobs. I wish to point out that there is no recruitment in the case of Ministry of Rural Development from 1997-2000. It is in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 2327, dated 14th April, 2002. With regard to the Assistant Advisor post, there is a shortfall of one, as on 29th August, 1997. And no vacancies have been filled up in 1997, 1998, 1999 and in 2000. The figures are there up to 2000. In the case of P.S., reserved for SCs, I am just trying to draw your attention, the shortfall is three and only one vacancy could be filled up in 1998. No other vacancy has been filled up. In the case of STs, the shortfall was two; no vacancy has been filled up. It is a horrifying situation. Even otherwise, the entire country is reeling under the heavy burden of unemployment. The Government is not making any recruitment. So, I would say, this is a hoax, this is a deceit, another deceit, that you are including some more names. What is the use of including these names, unless you can ensure that they get some jobs? This is all that I am trying to point out. Before concluding my speech, as regards the Sardar Sarovar Project, I say that unfortunately, in this country of ours, the planners are mostly from the upper class castes and because they have more scope for higher education. The upper castes have been getting more scope for education, for generations. But these poor people have been deprived for generations, for thousands of years. So, the planners, perhaps, are doing it in such a way that the areas being inhabited by the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward castes, are inundated and many civilisations are lost. I can speak for hours on this development and destruction; what you have destroyed, in the name of development. We have destroyed many civilisations; we have destroyed many arts, many forms of folk arts; we have destroyed many inhabitations; we have destroyed many castes, and those castes could not be rehabilitated in a proper fashion as they should have been.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I am just concluding, Sir. I am just expressing my agony. Sir, this is a serious situation. On this, I plead, Sir, that some special discussion should take place to find out how much

we could develop, and how we have destroyed a great number of people of this country. Sir, I am reminded of one Budhu Oraon, a Santhal woman. She was allowed, cosmetically, by Pt. Jawaharlal Nehru to inaugurate the Damodar Valley Corporation dam. Sometimes, I remember that. But what is the condition of that Budu Oraon, today? What is the condition of her family? What is the condition of her community? Her community is languishing. They are not getting any jobs. They do not have any place to live. Their civilisation has been lost. Wherever their ancestors lived, those places have been inundated. So, this is a torture, this is an atrocity, that is being perpetrated on those poor people, on people who, because of the stigma of caste, have been discriminated against for generations and for thousands of years in this country. Sir, shall we continue to perpetrate this sort of atrocity on these poorer castes and these poor people of our country, even after 55 years of Independence? Or, should we look into their situation, take stock of the situation and take some corrective measures? We should endeavour to take some corrective measures. This requires the conscience of this House, this requires a special discussion in this House.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मनोज भट्टाचार्य जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I expect that you will kindly allow a special discussion on this subject in this House. With these words, I conclude.

SHRI R. S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I extend my thanks to the hon. Minister, Dr. Satya Narayan Jatiya, for bringing this Bill for consideration and passage. In view of the consideration of the Bills together, we have an opportunity to discuss the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Of course, like my friend, Shri Manoj Bhattacharya, I can also speak for hours. But I do not want to. At the same time, I want to pinpoint and highlight the ideology behind the reservation policy. At the outset, I must say that the founding fathers of our Constitution, particularly the chief architect of our Constitution, Babasaheb Ambedkar, thought about this national problem. What was that national problem? That national problem was that the various castes and tribes that were living for generations together in the country, were being outcasted, tarnished, atrocities were committed on them, and they were not being allowed to come into in the mainstream of the nation. Therefore, the chief architect of the Indian Constitution,

Dr. Babasaheb Ambedkar, said, "It is not a problem of a particular caste or creed or tribe; it is a national problem. And, therefore, due compensation should be given to these Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This compensation should be given, not as a matter of charity, but as a matter of right, because, through generations, they have not been allowed to come into the mainstream of the nation.

Sir, in 1950, it was decided that a Presidential Order should be brought in this regard. There are two relevant articles, article 341 and article 342, in the Constitution. What does article 341 of the Constitution say? It says that the castes, which are socially and economically backward, should be included in the Schedule of a particular State, and, thereby, they would be identified as the Scheduled Castes of that State. What about article 342? The same logic applies to this also. It says that the tribes, which are socially backward, should be put in the Schedule of a particular State, and should be known as Scheduled Tribes of that State. Now, the Bill which has come before this House deals with the inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have been affected by the Sardar Sarovar Project, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, specified in relation to the State of Gujarat. This is my first point.

What is the purpose of the other Bill? The purpose of the other Bill is this. The States of Punjab and Orissa have suggested that some castes, which have still not been specified in article 341 of the Constitution, should be included in it. In fact, I wanted to raise this issue through a Private Member's Bill, but it has not yet come before the House for consideration. Now, what is the purpose of these two articles? I want to say that once and for all, this problem should be resolved. The purpose of this Bill is that the Scheduled Castes of a particular State should, automatically, be included in the list of Scheduled Castes of another State. Because of some provision in the Constitution, mobility is bound to be there; migration is bound to be there. I belong to the State of Maharashtra, which is a cosmopolitan State. Scheduled Castes belonging to different States like, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala and many other States are residing in Mumbai. But they are being deprived of this facility, and are not included in the list of Scheduled Castes of Maharashtra. This is the case in every State. The hon. Minister is a very competent Minister and he knows their problems well. I want to say, 'once a Scheduled Caste is always a Scheduled Caste.' There will be no change in that. So, there is no need to bring a Bill again and again. Apply your mind and find out the castes which have not

been included in the Scheduled Castes or Scheduled Tribes list of 1950. Prepare a comprehensive list of all those people. These people should not be neglected and deprived.

Sir, my second point is -- as mentioned by the earlier speaker also -- this provision should not be kept in the Constitution as an ornamental provision. It has to be seen how far the reservation policy for the Scheduled Castes and Tribes is being implemented. That is the main problem. I can say with full responsibility that up to 1970, this was kept in the Constitution as an ornamental feature. And, because of the hue and cry made by Members of both the Houses, this is going to be implemented. Now, I want to remind the hon. Minister -- unfortunately, Shri Sangh Priya Gautam is not here -- that all the Scheduled Caste Members of this House are members of SC/ST Forum.

Since the last three-four years, we have been striving for the implementation of the clearance of backlog policy, and reservation in promotion policy. Mr. Vice-Chairman, Sir, there is a backlog of 1,50,000,00 vacancies, throughout India. Forget Mr. Bhattacharya who said that new jobs should be created. Even the vacancies which are available, are not being filled up....(*Time bell*)..:.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप समाप्त करें।

SHRI R.S. GAVAI: Sir, I will conclude in two minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया आसन ग्रहण करें।

SHRI R. S. GAVAI: I am concluding, Sir. Then, Sir, six detrimental Office Memoranda were issued by the Department of Personnel and Training. Out of that, four Memoranda were withdrawn, but two Memoranda still remain. I want to know whether those two Memoranda have been implemented or not. I would also like to know from the hon. Minister, Dr. Satya Narayan Jatiya, whether the Bills that we have passed have been implemented or not; whether the administrative orders have been issued or not.

Our long-pending demand is that we should have a comprehensive legislation with regard to the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Prime Minister had assured in that legislation that there would be comprehensive reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as far as Maharashtra is concerned. In Maharashtra, as we had accepted Buddhism, alongwith Dr. Baba Saheb Ambedkar, the

strength of the reserved category seats, both in the State Legislature and in the Parliament, has been reduced. In 1990, it was restored. Why don't we restore the old position, as far as reservation of seats in the State Legislature of Maharashtra and in Parliament is concerned? Sir with these words, I conclude. Thank you very much. I support both the Bills.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय सदस्यगण, वैसे तो सभी दलों का समय समाप्त हो गया है, कांग्रेस पार्टी का भी समय समाप्त हो गया है, लेकिन अभी दो नाम और कांग्रेस पार्टी के आ गए हैं, इसलिए कृपा करके दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री नन्दी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार राज्य सभा में आया हूं, लोक सभा में तो था, लेकिन राज्य सभा के लिए एक नया मुझे कुछ यहां पर दिख रहा है। महोदय, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय सत्यनारायण जटिया जी ने मध्य प्रदेश में जहां दो कास्ट्स को इसमें इन्क्लूड करने की बात कही है, उससे दो राय तो नहीं हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि आजादी के 50 साल बाद, संविधान में एस.सी. एंड एस.टी. के लिए जो आरक्षण प्रदान किया गया, उन तमाम हमारी जातियों की एक दफा उसमें हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, आज लोक सभा में या राज्य सभा में या विधान सभा में रिज़र्वेशन तो है ही, लेकिन आज इतने साल के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक प्रगति, उनकी फाइनांशेल कंडीशन एक दफा देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर है। इस समाज के अंदर दूसरे वर्ग के साथ इक्वैलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो बाबा साहेब अम्बेदकर के उस जमाने में अनूसूचित जाति का कितना अंतर था, कितना उन्होंने अपने जीवनकाल के अंदर संघर्ष किया। आज भारत के अंदर अभी भी शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की कमी होने के नाते, आज चाहे हमारी केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर सख्ती से हम कोई कानून बनाकर दसवीं श्रेणी तक शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तब तक चाहे और पचास साल भी रिज़र्वेशन हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज हम देखते हैं बीड़ी वर्कर्ज़, कंस्ट्रक्शन लेबर और दूसरे होटल्ज़ में हमारे जितने बालक, जितने बच्चे काम करते हैं, उनकी आयु 8 और 9 साल की है। ये तमाम बच्चे वहां पर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पेट्रोल पंप हैं, कई जगह आपके बैंक्स हैं, वहां पर इन बच्चों को मजबूरी में काम करना पड़ता है। हमारे भारत की तरफ से एक भारत लेदर कार्पोरेशन स्थापित किया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि उस लेदर कार्पोरेशन का भी पूरा दिवाला निकल गया है। आज जितने हमारे चमार भाई हैं या लेदर वर्कर्स हैं और चमड़े का काम करते हैं, उनका कोई नहीं है। आज बाटा और टाटा के हाथ में उसकी मोनोपोली चली गयी है। आज सही मायने में हमारी स्थिति का अंदाजा दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से नहीं लगाया जा सकता है। उसके लिए आपको इंटीरियर में जाना होगा। आप मण्डल हैडक्वार्टर, तालुका हैडक्वार्टर और गांव के अंदर जाकर देखें, शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों की उस दुखद् परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं दोबारा एक दफा मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आज जिन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों के पास चाहे पेट्रोल पंप हों या दुकानें हो, लेकिन वास्तव में उनकी कितनी उन्नति हुई है, उन्होंने कितनी प्रगति की है, हमें एक दफा इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दसवीं क्लास तक की शिक्षा उनको अनिवार्य रूप से प्राप्त

हो, इस लिहाज से कानून को देखना पड़ेगा क्योंकि अगर सोसायटी में आदमी के पास शिक्षा है, धन है तो ही उसे समाज में समान दर्जा प्राप्त हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और जनजाति का सब्जैक्ट बहुत बड़ा सब्जैक्ट है। इसमें रिजर्वेशन कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें देखना होगा कि रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन कहां तक हुआ है। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि पेट्रोल पंप उसके नाम अलॉट होने के बाद भी उसे कोई बड़े बाबू चला रहे हैं। ऐसे मामलों में भी हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिए। अभी भी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय में एक दफा और चर्चा कराए। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

SHRI RISHANG KEISHING (Manipur): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the two Bills that have been presented before the House. However, while lending my support, I would like to make a few observations. I would like to draw the pointed attention of the Minister in charge of the Bill to one aspect, as to why the Government is bringing such a piecemeal legislation in the House. I am sure, there are similar demands from several other States. But these two Bills deal with only Gujarat and Orissa. Sir, these are not the only States which are inhabited by tribals and Scheduled Castes. I come from the North-East, which is inhabited by a large number of tribals. In my State, Manipur, there has been a consistent and persistent demand for many years from many tribes, for their inclusion in the list. I do not know whether the Minister and the Home Ministry have received any such demands. As far as I am concerned, as I have been in the State Administration and in the Assembly, I know that a large number of cases have come up in this regard. We discussed it in the Hill Areas Committee of the Assembly. We forwarded the whole thing to the Home Ministry. The State Government has recommended it. But, till today, nothing has happened. The State does not figure at all. Sir, on Friday, I submitted an amendment in this regard. But I do not find it here. Maybe, it was submitted late. Sir, through the proposed amendment, I suggested that the four tribes, particularly, from Manipur, namely, *Tarao*, *Paomei*, *Chongthu* and *Thanggal*, should be included in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in Part X - Manipur. Earlier, in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, only 29 tribes were included. Now, these tribes are to be included in this list. Sir, the reason is, in our State, the tribes maintain their own prestige; they do not want to go by the name of others. For so many years, they have been deprived of the facilities and privileges that have been extended to the other tribes.

They go on appealing, but there has been nobody to help them. That is why I say that they have been neglected. Yet, it is not too late, if you to decide to help them even now.

Sir, we are now celebrating the Golden Jubilee of our democracy. For 50 years these tribes have been neglected. These people have been demanding recognitions of their tribes in their individual States. To help them, the hon. Minister would do well if he brings forth another Bill, including Manipur and other States wherever such demands are there. That is my only submission. I want an assurance from the hon. Minister, in this regard, so that these people are not deprived of the justice any longer. I hope the hon. Minister will give an assurance to this effect while replying to the debate.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्य नारायण जटिया): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इन दो विधेयकों के माध्यम से 'जो चर्चा माननीय सदन में हुई है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के बारे में जो जो भी स्थिति है, उस पर ठीक प्रकार से एकबारगी में विचार-विमर्श होना चाहिए, तो सरकार की यह कोशिश है कि इस प्रकार के विषयों पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श के लिए उपाय किए जाएंगे। यह जो दो विधेयक हैं, इसमें एक तो सरदार सरोवर परियोजना के बन जाने से जो विस्थापित लोग हैं उनके पुनर्वास और उनको वही दर्जा देने का है जो कि वह अभी अनुसूचित जाति, जनजाति का प्राप्त कर रहे हैं और दूसरा कुछ जातियों को इस सूची में सम्मिलित करने का है। मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं, जिनमें माननीय गौतम जी, माननीय परमार जी, माननीय गवई जी और दूसरे सभी माननीय सदस्यों के जो विचार आए हैं, उनको मैंने नोटिस में लिया है और अब हमारी चिंता होगी कि इन सारी बातों के लिए समय-समय पर उपाय किए जाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे पास 505 प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके इनक्लूजन का प्रस्ताव है और जो विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं। कुछ राज्य सरकारों के पास हैं, कुछ आयोग के पास हैं, कुछ संसद के पास विचाराधीन हैं। इसके लिए मेरे मंत्रालय की कोशिश होगी कि यह कार्य शीघ्र पूर्ण हो। चूंकि यह एक शुरूआत है, पहले कोई प्रक्रिया तय नहीं थी, अब हमने प्रक्रिया सुनिश्चित कर ली है कि किस प्रकार से इन प्रस्तावों की जांच की जाए। हमने एक प्रणाली बना ली है कि राज्य सरकारों के माध्यम से, महापंजीयक, जनसंख्या के माध्यम से, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के माध्यम से प्रस्ताव के आने के बाद सरकार उस पर पूरा विचार करती है और फिर संसद उसको पारित करती है। इस विचार-विमर्श में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उन सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किए जाएं।

श्री राजू परमार : मंत्री जी, हमारा जो गुजरात का मोची वाला बिल आपके डिपार्टमेंट में पड़ा है, उसमें भी अमेण्डमेंट करके ले आइएगा।

डा. सत्य नारायण जटिया : जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब मैं पहले संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 के लिए प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ कि -

> संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाए जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, विधेयक, जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) :अब, हम विधेयक पर धारा वार विचार करेंगे।

धारा 2 और धारा 3 विधेयक के अंग बने।
धारा 1 अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

डा. सत्य नारायण जटिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> ' कि विधेयक कों पारित किया जाए।'

प्रस्ताय पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब मैं 'संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 को विचार के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :-

> 'कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए। '

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
धारा 2 विधेयक का अंग बनी।
धारा 1 अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।

डा. सत्य नारायण जटिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> ' कि विधेयक को पारित किया जाए।'

प्रस्ताव पर मत लिया गया और यह स्वीकृत हुआ।

THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 2002

THE MINISTER OF AGRICULTURE (Shri Ajit Singh): Sir, I move:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to co-operative societies with objects not confined to one State and serving the interests of members in more than one State, to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of co-operatives as people's institutions based on self-help and mutual aid and to enable them to promote their economic and social betterment and to provide functional autonomy and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

Mr. Vice-Chairman, Sir, the Multi-State Cooperative Societies Bill, 2000 is intended to replace the existing Multi-State Cooperative Societies Act, 1984. "Cooperative Societies" is a State subject under Entry 32 of the State List. The States have accordingly enacted their own Acts. In order to facilitate the organisation and functioning of the cooperative societies having jurisdiction in more than one State, Parliament enacted the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 under Entry 44 of the First List of the Constitution.

In view of the increasing demand from the cooperative sector and recognising the need for promoting democratic and autonomous functioning of the cooperatives, the Planning Commission appointed a Committee in 1990 under the chairmanship of Ch. Brahm Perkash to examine the whole issue. The Committee submitted its report in 1991 and, *inter alia,* recommended a "Model Cooperatives Law" for the States, aimed at providing a genuine character to cooperatives with the deletion of restrictive provisions in the existing State Acts and to facilitate the building of an integrated cooperative structure. The Government of India, in the Department of Agriculture and Cooperation, constituted an Advisory Committee under Shri R. N. Mirdha to advise the Central Government on matters relating to ensuring autonomous functioning of the multi-State cooperatives.

Based on the recommendations of Ch. Brahm Parkash Committee and Mirdha Committee, a legislative proposal to replace the existing Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 was formulated and accordingly, the